industries—big, small and medium— are affected by it. That is why due importance has been given by the previous Government and also by the present Government, to production of power. That is all I can say. *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. Question No. 344. *(Interruptions)*

*344 *[The questioner (Shri Saifulla) was absent. For answer vide col ..... infra]*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 345. *(Interruptions)*

Please sit down. This is not the way.

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHA JIRAO SHINDE: Madam, I wanted to speak about Question No. 344 *(Interrup tions)* In the list of Unstarred Ques tions .....

THE DEPUTY CHAIRMAN: But the questioner is not here.

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Yes. A similar question has been approved as Starred Question. It is on the same subject, 'Formation of a Dispute Settlement Panel at the behest of USA'. What is the part (a) of the Question? It is, whether India agreed to the formation of a Dispute Settlement Panel....

THE DEPUTY CHAIRMAN. What are you asking? You are not the questioner.

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Madam, this question has been approved as a Starred Question. There is a similar one in the list of Unstarred Questions and that is mine. So, what I am saying is ...*(Interruptions)* Madam, the question is ....*(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: I know you are a star performer. But unfortunately the ballot did not think that way.

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: That is true, Madam, but it should have been clubbed with this. I could have an opportunity to ask at least one supplementary. Never mind, a half-an-hour discussion can be allowed on this because this is an important subject and we would like to have a discussion at length. Thank you, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Question No. 345.

Prices of Bread in Delhi

*345. SHRI RAM NATH KOVIND: DR. RANBIR SINGH:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether the prices of bread of 400 grams and 800 grams have been increased four times during June to September, 1996 in Delhi;

(b) if so, the reasons therefor with the names of the authorities approving such revision;

(c) whether Government propose to get grounds of such revision investigated; and

(d) if so, the details thereof; and if not, the reasons therefor?

खाद्य मंत्री और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) इस मंत्रालय द्वारा डबलरोटी के मूल्यों को मानीटर नहीं किया जा रहा है। तथापि, मार्डन फूड इंडस्ट्रीज लि॰ तथा अन्य बाजार स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर यह देखा गया है कि दिल्ली में जून से सितम्बर, 1996 की अवधि के दौरान 400 ग्राम तथा 800 ग्राम की डबलरोटी के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) से (घ) इस समय देश में डबलरोटी के विनिर्माण तथा मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है। डबलरोटी

*The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Ram Nath Kovind.

के विक्रय मूल्य गेहूं, मैदा, चीनी जैसे आदानों की लागत तथा अन्य प्रचालन आदि से संबंधित लागतों और वितरण लागत के आधार पर विनिर्माताओं द्वारा नियत किए जाते हैं।

श्री रामनाथ कोविन्द: महोदया, मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि पिछले जून और सितम्बर, 1996 के बीच डबलरोटी की कीमतों में कोई वृद्धि दिल्ली में नहीं हुई है। महोदया, मेरा यह कहना है कि यह उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है। मेरा पहला पूरक प्रश्न यह है कि मंत्री जी कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि चार सौ और 8 सौ ग्राम की डबलरोटी की कीमत जून, 1996 और सितम्बर, 1996 में दिल्ली में क्या थीं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपसभापति महोदया, यह योजना 15 अगस्त, 1994 से चलाई गई थी। 15 अगस्त, 1994 को तत्कालीन प्रधान मंत्री जी ने यह घोषणा की थी और उसी घोषणा के तहत यह योजना चलाई गई थी जिस में चार सौ ग्राम डबलरोटी की कीमत बाजार भाव से 25 पैसे कम थी और 50 पैसे आठ सौ ग्राम डबलरोटी की कम थी जो भाव पीछे चल रहा था।

श्री रामनाथ कोविन्द: उपसभापति महोदया, मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। मैंने दोनों का उत्तर पूछा है, केवल एक माडर्न बेकरी की जो प्राइसेस थीं, उसी का नहीं पूछा है। जो बाजार की आम कीमतें थीं, उस का उत्तर पूछा है।

उपसभापति: बाजार की आम कीमतें क्या थीं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपसभापति महोदया, उधर सितम्बर में, यह स्वाभाविक है जमाखोरी और कालाबाजारी के चलते गेहूं का कृत्रिम अभाव पैदा किया गया जिस के कारण डबलरोटी पर भी इस का प्रभाव पड़ा।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: प्रश्न बड़ा सीधा है, उस समय क्या कीमत थी और आज क्या कीमत है?

उपसभापति: वह ब्रेड नहीं खाते होंगे।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: केक खाते हैं?

उपसभापति: नहीं, सब लोग चपाती खाते हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपसभापति महोदया, मैं पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दूं कि फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय से संबंधित प्रश्न है। फूड प्रोसेसिंग से यह मामला जुड़ा हुआ है, लेकिन खैर प्रश्न आ गया है। वैसे डबलरोटी का मामला फूड डिपार्टमेंट नहीं देखता है, तब भी मैं दाम बता रहा हूं: मॉडर्न ब्रेड का आठ सौ ग्राम की डबलरोटी का दाम जून में रु॰ 6.50 पैसे था और सितम्बर में भी वहीं रुपए 6.50 था। जो चार सौ ग्राम थी, उस का अलग-अलग है, जैसे माडर्न स्पेशल है, ब्रिटानिया है, गोल्ड वर्क प्रीमियम का अलग दाम है। इस का रु॰ 5.50 था, गोल्ड वर्क प्रीमियम का आठ सौ ग्राम का रु॰ 5.50 था, व्हीट मेन का 7 रुपया। तो यह जो अलग-अलग डबलरोटी है, उन के अलग-अलग दाम हैं। दाम के डिटेल्स में माननीय सदस्य को दे दूंगा। इस में सभी का समय जाया करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जो आठ सौ ग्राम का खुले बाजार में अर्थात् खुदरा में 8 रुपए था और यहां दिया जाता था डबलरोटी रुपए 4.50 में। चार सौ ग्राम का जो मॉडर्न स्पेशल है, उस का अलग दाम है। इस का आठ सौ ग्राम का 10 रुपया है। जो ब्रिटानिया है उसका 11 रुपए, गोल्ड वर्क प्रीमियम का 11 रुपए और फिर जहां चार सौ ग्राम का 6 रुपए और रु॰ 5.50 पैसे ...(व्यवधान)...

उपसभापति: उन्होंने पूरी रिपोर्ट दे दी है।

श्री सिकन्दर बख्त: अगर यह एक ब्रांड की डबलरोटी का जिक्र कर रहे हैं तो जितनी भी ब्रांड्स की डबलरोटियां इस वक्त एवेलेबल हैं, उन सब का जिक्र करना चाहिए। जब उन्होंने आम रोटी के बारे में पूछा है तो आम रोटी का ही जवाब दें। अगर एक पर्टिकुलर ब्रांड को लेकर चलते हैं तो तमाम जितने भी ब्रांड्स आ रहे हैं, हरेक का बताइए?

†اشری سکندر بخت: اگر یہ ایک برانڈ ڈبل روٹی کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو جتنی بھی برانڈڈ ڈبل روٹیاں اس وقت اویل ایبل ہیں ان سب کا ذکر کرنا چاہیے۔ جب انھوں نے عام روٹی کے بارے میں پوچھا ہے تو عام روٹی کا ہی جواب دیں۔ اگر ایک پرٹیکلر برانڈ کو لیکر چلتے ہیں۔ تو تمام جتنے بھی برانڈس آ رہے ہیں ہر ایک کو بتایئے۔

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

THE DEPUTY CHAIRMAN: In fact, this question docs not relate to his Ministry. *(Interruptions)* but even then, he is answering.

SHRI S1KANDER BAKHT. Then, it should not have been accepted.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः यह फूड प्रसेसिंग मंत्रालय से संबंधित है। मैंने जवाब दिया है कि फूड इंडस्ट्री में जो मार्केट भाव है, सुपर बाजार में डबल रोटी का जो खुदरा मूल्य है ...(व्यवधान)...

उपसभापतिः उन्होंने प्राइवेट का नहीं दिया है, सरकारी के आंकड़े उन के पास हैं।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदीः फिर प्राइवेट के आंकड़े कहां से आए?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः जो जानकारी मुझे फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय से प्राप्त हुई है, वह मैं जवाब दे रहा हूं।

उपसभापतिः ठीक है, जो बताया है वह सरकारी है, उस का जवाब दे सकते हैं। प्राइवेट में कोई क्या बेच रहा है, वह उनके मंत्रालय से संबंधित नहीं है।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदीः बाजार भाव क्या है, यह तो प्रश्न जब उन्होंने मंजूर किया है। ...(व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is a Minister of Food and Civil Supplies. *(Interruptions)*

श्री रामनाथ कोविन्दः मैडम, जो मंत्री जी ने जवाब दिया कि है पूरक प्रश्न के उत्तर में, वह उत्तर बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है जो उन्होंने मेन प्रश्न के उत्तर में दिया है। अभी उन्होंने एडमिट किया है कि जून और सितंबर के बीच में दामों में बढ़ोत्तरी हुई। मैडम, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि यह डबल रोटी असेन्सियल कमोडिटी है या नहीं। यदि है, तो फिर यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसकी प्राइसेस पर भी कंट्रोल किया जाए। ...(व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I don't think *Double Roti* is an essential commodity. Bread, I mean *Rotis* and *Chap-patis* are essential commodities. *Double Roti* is not.

श्री सिकन्दर बख्तः मैडम, गेहूं की जो हालत हो रही है, उसमें चपाती की हालत भी खराब है। ....(व्यवधान)....

†اکبری سکندر بخت : میڈم - لیگیوں کی جو حالت ہو رہی ہے - اسمیں چپاتی کی حالت بھی خراب ہے - - - - "مداخلت"!..

THE DEPUTY CHAIRMAN: I don't think *Double Roti* should be an essential commodity in India. Not all of us take it.

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदीः मैडम, शहर में लोग सुबह इसी को खाकर काम पर निकलते है। ....(व्यवधान)....

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्राः मैडम, यह रिक्शे वाले, तांगे वाले, जितने भी गालियों में घूमने वाले लोग हैं, ये सब ब्रेड लेकर ही खाते हैं। ....(व्यवधान).....

आप अपना सवाल पूछिए।

श्री अजीत जोगीः सत्तू का गेहूं, उसका पूछिए। ...(व्यवधान)...

श्री रामनाथ कोविन्दः मैडम, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि यदि यह असेन्सियल कमोडिटी है तो सरकार की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि इनके प्राइसेस पर भी नियंत्रण किया जाए। यदि नहीं है, तो इसको असेन्सियल कमोडिटी में लाया जाए और इनकी प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए। इस पर मैं मंत्री जी की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः उपसभापति महोदया, मूल्य निर्धारण निर्माताओं के द्वारा होता है। जो संबंधित हैं, आपरेटिंग कोस्ट के आधार पर, मैनेफैक्चरर्स, जो डबल रोटी बनाने वाले हैं, वह तय करते हैं। यहां तक सरकारी दाम का सवाल है, जैसा आपने कहा कि असेन्सियल कमोडिटी में है, गेहूं असेन्सियल कमोडिटी है, सुपर बाजार में और इससे जो मैनुफेक्चरर्स और भी समान हैं, उसके संदर्भ में हमने आपको अभी दाम बताया। सुपर बाजार में मॉडर्न फूड इंडस्ट्री का है। अकेला मॉडर्न फूड इंडस्ट्री है, जिसको गेहूं एक हजार रुपया टन कम दाम पर दिया गया सरकार के जरिए, एफ॰सी॰आई॰ के जरिए और वह योजना 15 अगस्त, 1994 को तत्कालीन प्रधान मंत्री ने घोषित की थी। इस घोषणा के चलते 15 अक्तूबर से 25 अक्तूबर के बीच सभी जगह यह

†[ ] Troifeliteration in Arabic Script.

उपसभापतिः जवाब दे दिया है

लागू हुआ कि मार्डन फूड इंडस्ट्री जो है उसको कम पर दिया जाएगा और वह 400 ग्राम वाली डबल रोटी 25 पैसे कम पर, 800 ग्राम वाली जो डबल रोटी है वह 50 पैसे कम पर बिक्री करेगी और उसको एफ०सी०आई० एक हजार रुपया प्रति टन कम पर गेहूं, सस्ते दाम पर मुहैया करेगी। अभी 31 अक्तूबर, 1996 को यह योजना इसीलिए समाप्त हुई क्योंकि इस संबंध में उड़ीसा हाईकोर्ट में एक मामला दर्ज किया गया है। प्राइवेट जो रोटी बनाने वाले हैं, और भी दूसरे जो बेकरी वाले लोग हैं, उन लोगों ने एक मुकदमा दर्ज किया है उड़ीसा हाईकोर्ट में।

श्री रामनाथ कोविन्दः मैडम, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

I I think he has answered very correctly and elaborately. Don't say he did not answer. I am a witness to that.

डा० रणबीर सिंहः मैडम, जो जवाब दिया गया है, यह बड़ा डिसएपांटिंग है। ब्रेड की कीमतों को यह मिनिस्ट्री मोनीटर नहीं करती।

उपसभापतिः सुनाई नहीं दे रहा। जरा जोर से बोलिए, प्लीज।

डा० रणबीर सिंहः मैडम, ब्रेड की कीमतों को यह मिनिस्टरी मोनीटर नहीं करती। किसी को तो मोनीटर करना चाहिए। कन्ज्युमर को किसके रहम पर छोड़ा गया है? मैं यह पूछना चाहता हूं कि 400 ग्राम की डबलरोटी में कितना आटा, कितना मैदा, कितनी शुगर, कितनी ओपरेटिंग कोस्ट, कितना प्रोफिट और कितनी डिस्ट्रिब्यूशन कोस्ट है उसकी? और, किस बुनियाद पर उसकी कीमत तय की गई है?

मैडम, "बी" पार्ट इसका यह है कि दूसरे-दूसरे ब्रांड की डबलरोटियों में बहुत डिफरेन्स है। क्या मोडर्न बेकरी की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपके पास कोई सुझाव है या कोई इच्छा है ताकि ज्यादा प्रोडक्शन हो और यह जो दूसरे ब्रेड वाले हैं वह कन्ज्युमर को उस तरह से एक्सप्लायट न कर सकें? यह मेरे सवाल हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः उपसभापति महोदया, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, इसके संदर्भ में जो मूल प्रश्न है उस बारे में मैं समझता हूं कि सभी चीजों का दाम हम फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री से प्राप्त करके ही दे सकते हैं यह जानकारी यहां नहीं है, मैं फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री से प्राप्त करके उन्हें भेज दूंगा। ब्रेड की कीमतों को नियंत्रित करने का जहां तक सवाल है, तो फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री के कार्य क्षेत्र में भी कंट्रोल करने की, मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार के नियंत्रण के लिए खाद्य प्रोसैसिंग मंत्रालय में कोई तंत्र नहीं है।

डा० रणबीर सिंहः "मार्डन बेकरी" की केपेसिटी बढ़ाने के बारे में भी मैंने पूछा था?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः "मार्डन बेकरी" की केपेसिटी के बारे में कुछ नहीं पता।

श्री बंगारू लक्ष्मणः महोदया, पिछले दिनों इस सदन में आटे और गेहूं के दाम को लेकर के चर्चा हुई थी। मैं मंत्री महोदय, से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यह जो वीट के दाम बढ़ गए हैं, इसके जो बल्क कंज्यूमर्स हैं, उन बल्क कंज्यूमर्स को वीट सीधा-सीधा नहीं दिया जाता है। एफ०सी०आई० ओपन मार्किट में प्राइसिस कम करने की दृष्टि से ट्रेडर्स को वीट देती है और ट्रेडर्स के पास से बिस्किट मैन्युफेक्चरर्स और बेकरीज़ खरीदती हैं। यह नहीं है कि केवल दिल्ली में ही फूड प्राइसिस बढ़ गए हैं, हर शहर के अंदर ब्रेड के प्राइसिस बढ़ गए हैं, बिस्किट्स के दाम भी बढ़ गए हैं क्योंकि सीधा जो एफ०सी०आई० को बल्क कंज्यूमर्स के पास वीट देना चाहिए, वह नहीं दिया जा रहा है और जो वीट फ्लोर मिल-मालिकों को दिया जाता है, वह 572 के रेट दे दिया जाता है और वे फ्लोर वाले आटा तैयार करके उसे 900 के हिसाब से बिस्किट मैन्युफेक्चरर्स को, बेकरीज़ को पहुंचाते हैं। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कितना मुनाफा वे कमा रहे हैं। बिस्किट मैन्युफेक्चरर्स, जो बिल्कुल स्माल स्केल इंडस्ट्री में है— हैदराबाद और आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा बिस्किट मैन्युफेक्चरिंग सैंटर है, जहां 10,000 मजदूर काम करते हैं, पचासों एस० एस०आई० यूनिट्स इस बिस्किट इंडस्ट्री में है—और वे लोग मांग कर रहे हैं एफ०सी०आई० से कि सीधा, चूंकि हम लोग डायरेक्ट कंज्यूमर है, डायरेक्ट यूज़र है, इसलिए हमको प्रियरिटी बेसिस पर कोटा दिया जाना चाहिए। हमारी स्टेट गवर्नमेंट के सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ने भी एफ०सी०आई० को प्रिजेंट किया, लेकिन वहां की एफ०सी०आई० यह कहती है कि सैंटर के गाइड लाइंस जो है, उसमें ऐंड-यूजर्स को देने की बात नहीं है, ट्रेडर्स को हम लोग देंगे। ट्रेडर्स को जहां पर 572 रुपए में दिया जा रहा है, वह जब यूजर्स के पास जाता है तो 900 रुपए का हो जाता है।

उपसभापतिः अगर आप इतना लम्बा बोलेंगे तो मंत्री जी जवाब कब देंगे? बैठिए, उन्हें जवाब देने दीजिए। Let him answer, please.

श्री बंगारू लक्ष्मण: मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इस बारे में वे क्या कहना चाहते हैं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपसभापति महोदया, माननीय सदस्य ने, जो मूल प्रश्न है, उससे बाहर सवाल पूछा है, लेकिन मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं। जो रोलर मिल्स हैं, पहली बार, उपसभापति महोदया, एफ०सी०आई० के जरिए जो खुली बिक्री की जाती थी गेहूं की, उसको मैंने स्ट्रीम लाइन कर दिया है और तीन सदस्यों की एक समिति बना दी है, जिसमें स्टेट के डायरेक्टर आफ फूड मैम्बर हैं, एक और अधिकारी उसमें मैम्बर है, एक और मैम्बर हैं जो एफ०सी०आई० से हैं। तो एक तीन सदस्यों की समिति बना दी गई है और उस कमेटी को इंस्ट्रक्शन्स दी गई हैं कि जो लोग गेहूं लेना चाहते हैं, वे अपना आवेदन 1 तारीख से 7 तारीख तक दें, वह आवेदन 7 के बाद एग्जामिन होकर 14 तारीख तक निष्पादित हो जाएगा और गेहूं उन्हीं को दिया जाएगा, खासकर के कोआपरेटिव वालों को, कोआपरेटिव संस्था जो स्टेट्स में हैं, जहां भी हैं। इस तरह की जो जानकारी माननीय सदस्य दे रहे हैं कि डायरेक्ट बल्क कंज्यूमर को नहीं देकर, कुछ डायरेक्ट कंज्यूमर को दिया जाए ताकि उसको वह सस्ती दर पर मिल सके, ऐसा आवेदन हमारे पास, हमारे जानकारी में मंत्रालय में नहीं आया है। यदि इस तरह की जानकारी है तो दी जाए, लेकिन उसको एक अंडरटेकिंग देनी होगी। उसको एक अंडरटेकिंग यह देनी होगी कि वह सस्ते दर पर जिस गेहूं की एफ०सी०आई० से खरीद करेंगे, उसकी रोटी उनको सस्ते दर पर उपलब्ध करानी होगी। यदि यह शर्त, यह अंडरटेकिंग होगी तो गेहूं निश्चित रूप से दिया जाएगा। यह पहली बार हमने स्ट्रीम लाइन किया है डिस्ट्रिब्यूशन को, नहीं तो पहले 10,000, 12,000 जितना चाहते थे, लेते थे रोलर मिलर। हमने 200 टन उसका निर्धारित कर दिया है, अभी 500 किया है। तो जब अंडरटेकिंग वे दे देंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सस्ते दर पर बिस्किट यदि मैन्युफेक्चरर्स, बिस्किट मैन्युफेक्चरर्स मार्केट में आप लोगों को उपलब्ध कराएं तो उनको देने में कोई नुकसान नहीं है। मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTION

Exploitation of Workers of the Cloth Mills at Surat

*342. SHRIMATI JAYANTI PAT-NAIK: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the approximate number of workers working in the various cloth mills at Surat in Gujarat;

(b) the mill-wise details thereof both in the public and private sectors;

(c) whether the workers in those mills are being exploited by the employers;

(d) whether the workers from Orissa who are working in those mills are not getting wages regularly and are asked to work for more than eight hours a day; and

(e) if so, the steps taken to protect those workers from the clutches of the employers?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (e) According to the information received from the Government of Gujarat, approximately 3300 workers are working in the various cloth mills at Surat in Gujarat. The mill-wise break-up of the workers in cloth mills at Surat is given below:—

S.No.	Name of the mills	No. of workers
1.	The Nirajan Mills, Surat.	650
2.	Standard Industries Ltd., Surat.	950
3.	The Surat Dist. Co. Operative Mills, Surat.	1500
4.	Garden Cotton and Yams Ltd., Surat.	200
	TOTAL:	3300

The State Government of Gujarat which is the appropriate Government for these Mills under the relavant Labour laws has intimated that by and large no complaints of exploitation of workers in